भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 96

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।

13 माघ, 1943 (शक)

आधार और मतदाता पहचान पत्र को आपस में जोड़ना

96. श्री के. सुधाकरन:

श्री बैन्नी बेहनन:

श्री एंटो एन्टोनी:

श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'आधार और मतदाता पहचान-पत्र को आपस में जोड़ने के कारण उससे होने वाले दुरूपयोग को रोकने के लिए किसी प्रावधान पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मतदाता पहचान पत्र में संकलित डेटा डेटाबेस को 'आधार से जुड़े डेटाबेस के डेटा के साथ जोड़ा जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने चुनावी प्रयोजनों के लिए आधार डेटा के संभावित दुरूपयोग जैसे मतदाता का गलत परिचय बनाने की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से **(घ):** मतदाता सूची भारत के चुनाव आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत तैयार की जाती है, जैसा कि संविधान के तहत स्थापित किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी और तकनीकी मंच है कि आधार डेटा का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे एकत्र किया जाता है। चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत चुनाव कानूनों में प्रस्तावित संशोधन आधार को मतदाता डेटा की सही पहचान के लिए एक विकल्प के रूप में रखता है। यह समझा जाता है कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है। इसलिए, आधार डेटा के शासन के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों,

प्रसुविधायों और सेवायों का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के कानूनी प्रावधानों का कानून के अनुसार पालन किया जाता है।

****